प्रसार भारती

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

13.11.2025 / प्रादेशिक समाचार / 09:20बजे

'' पहले मुख्य समाचार''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को दी मंजूरी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली कार विस्फोट में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया–मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम–मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर की समीक्षा।
- भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामलों में आई 21 प्रतिशत की कमी।
- प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के तीन हवाई अड्डों से नियमित उड़ानें न होने पर लिया संज्ञान–केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी है। इस प्रमुख पहल की घोषणा इस वर्ष के बजट में भारत के निर्यात को विशेष रूप से एम.एस.एम.ई के पहली बार के निर्यातकों और श्रम क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए की गई थी। नई दिल्ली में बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मिशन वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित खाका उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि ईपीएम कई योजनाओं से परिणाम–आधारित और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है।

––बाईट––आज ये एक्स्पोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है। 25 हजार 60 करोड़ रूपए का इसका आउटले है। 6 साल इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉप्रीहैंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्पोर्ट ईको सिस्टम को स्पोर्ट करने का डिसिजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन्हीं सैक्टर को दी जाएगी जिनके उपर एक एडवर्ड इंपैक्ट है जैसे टैक्सटाइल है लैदर है, जैंटस ज्यूलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में प्रदेश सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। यह समारोह 11 दिसंबर को मंडी जिले में आयोजित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों और दो वर्ष के रोडमैप को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दो वर्षीय रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार जनता के द्वार तक अधिक सेवाएं देने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सभी विभागों में सुशासन को और मजबूत करने पर जोर देगी।

टीबी–भारत

भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामलों में 21 प्रतिशत की कमी आई है जो वैश्विक औसत 12 प्रतिशत से लगभग दोगुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देशमें टीबी रोगियों की संख्या 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख 187 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के बेहतर केस–फाइंडिंग दृष्टिकोण ने निदान और उपचार कवरेज में वृद्धि की है। इसने आगे कहा कि बहु–औषधि प्रतिरोधी टीबी के मामलों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। तपेदिक के कारण होने वाली मृत्यु दर भी 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर पिछले वर्ष प्रति लाख 21 हो गई है। सरकार देश से टीबी को खत्म करने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और निक्षय पोषण योजना सहित कई पहलों को लागू कर रही है।

कैबिनेट– प्रस्ताव

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की आतंकवादी घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल पीड़ितों के प्रति श्रद्धांजलि और शोक व्यक्त करता है। मंत्रिमंडल ने हिंसा की निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया।

हाईकोर्ट

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के तीनों हवाई अड्डों शिमला, कुल्लू और कांगड़ा से नियमित उड़ानें न होने पर संज्ञान लेते हुए राज्य और केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ में जनहित याचिका की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाते

हुए उनसे विवरण देने को कहा है। इसके अलावा राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें यह बताया जाए कि नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से क्या आग्रह किया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नियमित रूप से उड़ानें संचालित करने का भी आदेश दिया है।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में सर्वांगीण विकास हुआ है। ये बात कल उन्होंने कोटखाई उपमंडल की रामनगर पंचायत में 35 लाख रूपए से अधिक राशि से निर्मित पंचायत भवन के उदघाटन अवसर पर कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण सहित बिजली व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए करोड़ों रूपए की राशि खर्च की जा रही है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने रामनगर में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिक्षा व्यक्तित्व विकास व समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है। शिमला के गेयटी थियेटर में कल एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए नियमों में संशोधन कर सरकारी व निजी स्कूलों के अंतर को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है।

कुलदीप पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के अंतर्गत पिछले अढ़ाई बर्षों के दौरान 32 ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा किया जा चुका है जबकि 18 ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये बात उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलेरा के वार्षिक समारोह के दौरान कही। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान 39 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत उद्घाटन भी किया। पठानिया ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में लगभग 125 नई ग्रामीण सड़कों की आवश्यकता है जिन्हें सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात अगले एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग तथा जल शक्ति विभाग के माध्यम से 260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 के अंत तक इस क्षेत्र में सड़क व पेयजल योजनाओं पर लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी।

वाटरशेड महोत्सव

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में 11 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि इस दौरान भूमि पूजन, लोकार्पण और वाटरशेड पुनरुत्थान मिशन का शुभारंभ जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड विकास घटक के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

मौसम

प्रदेश में इन दिनों मौसम खुश्क बना हुआ है जिसके चलते शाम के तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। जनजातीय जिलों सहित राज्य की ऊंची चोटियों पर शीतलहर चलने से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में तापमान आमतौर पर सामान्य चल रहा है जबकि रात्रि के तापमान में कई स्थानों पर दो से तीन डिग्री सैल्सियस गिरावट दर्ज की जा रही है।

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से .....

आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है नेरचौक मेडिकल कॉलेज से 41 डॉक्टर ट्रांसफर–मेडिकल कॉलेजों का अलग कैडर बनने पर सरकार ने एक साथ किए तबादले।

दैनिक भास्कर व पंजाब केसरी की एक खबर है पंचायतीराज चुनाव लड़ना पड़ेगा महंगा, सरकार ने जमानती राशि में की बढ़ोतरी।

''अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक के परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को दी मंजूरी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली कार विस्फोट में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया–मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम–मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर की समीक्षा।
- भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामलों में आई 21 प्रतिशत की कमी।
- प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के तीन हवाई अड्डों से नियमित उड़ानें न होने पर लिया संज्ञान–केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब।